LOK SABHA

Monday, August 4, 1969/Sravana 13, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

PL-480 Transactions

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*301 SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India has suggested to U.S. Government to soften the terms of PL-480 transactions during the next year;

(b) if so, whether the U S. Government has agreed to the request of the Government of India; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arsse.

श्री सीताराम केसरी : उपाध्यक्ष जी, पी० एल० 480 के अन्तर्गत इस देश में 1956 से लगायत 1968 के 30 जून तक 2024 करोड़ रु० के करीब का सामान आया और उसके अन्तर्गत वह रुपया जमा हुआ, उसमें से उन्होंने साढ़े 11 सौ करोड़ रुपया सरकार को लोन दिया, 450 करोड़ रुपया ग्रान्ट के रूपमें दिया, 1666 करोड़ रुपया उन्होंने इस मुल्क में बांटा, पी० एल० 480 के अन्तर्गत, 158 करोड़ रुपया सन 56 से लगायत 68 के 30 जून तक अमेरिकन एम्बेसी को खर्च करने के लिए उसके द्वारा रुपया मिला, हमारे देश में पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो सहायता मिलती है हमारी तरक्की के लिए, वह बहुत अच्छी चीज है लेकिन चूंकि इन्डियन करेन्सी में हमको यह माल मिलता है और फिर उस इंडियन करेन्सी का जो इस्तेमाल होता है जैसे कि अभी 67 के चुनावों के बाद हमारे देश में बहुत सी बातों की चर्चा की गई कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत सी० आई० ने इतना रुपया खर्च किया, रसिया इम्बैसी ने बेकारों के थे इण्डियन करेन्सी में इतना रुपया खर्च किया— तो मैं जानना चाहता हूं कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो रुपया आता है हमारी तरक्की के लिए और अमेरिकन इम्बैसी के द्वारा जो रुपया खर्च किया जाता है······(व्यवधान)······

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय सदस्य इतनी लम्बी भूमिका बांध रहे हैं, इसलिए दो तीन सवाल ही आखीर तक हो पाते हैं। ······(व्यवधान)······

श्री शिव नारायण : जब आप भूमिका बांधते हैं तब क्या होता है ?...(व्यवधान)...

क्या यह पार्लमेन्ट इनकी बपौती है ? क्या हमको राईट नहीं है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY SPEAKER : Please be brief in giving the backgrond and put your question, Mr. Kesri.

श्री सीताराम केसरी : मैंने इस हाउस में कई दफा आपसे अर्ज किया कि हर सवाल के लिये टाइम लिमिट कर दीजिए लेकिन आपने नहीं किया। मैं समय नहीं लेना चाहता लेकिन चूंकि आपने और लोगों को अधिक से अधिक समय दिया है और उस दिन भी मैंने निवेदन किया

था कि किसी भी प्रश्न के लिए समय नियत किया जाये—चूंकि हल्ला हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ।

तो मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन सभी बातों को देखते हुए एस्टिमेट्स कमेटी ने आपको राय दी है कि इस धन की वजह से इंफ्लेशन हो सकता है, इसलिए आप कमेटी बनाइए जो इस बात की छानबीन करे कि इस पैसे की वजह से हमारी आर्थिक अवस्था पर, हमारी तरक्की पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन होता है या नहीं होता है—उस सुझाव के अन्तर्गत जो आपने खुसरु कमेटी बनाई और उसने जो सुझाव दिये उसके अन्तर्गत क्या आप अगले साल में पी० एल० 480 का बजट अपने नये नोट के साथ उपस्थित करेंगे ?

SHRI P. C. SETHI : Sir, the hon. Member has made various points during his question. The main thing is, out of the total accruings of PL-480 funds, which were Rs. 1319.96 crores in the forms of loans and Rs. 380,81 crores in the form of grants, Rs. 1300 crores and Rs. 347 crores have been for expenditure in government projects. As far as the balance that is there is concerned that is all deposited in the Reserve Bank. But it is true that part of it goes to the American Embassy, Partly for their expenses and partly for aid to Nepal and a portion for conversion into dollars for payment of freights etc. Therefore, the total which accrues to the U. S. Embassy out of these Rs. 40 crores of last year is hardly about Rs. 15 crores. Even for this they have been submitting the accounts to us. Although it is not very necessary to go into those details of the accounts, according to my information the hon. Home Minister has made a clarfiication in the House about the amounts spent.

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष जी, पी० एल० 480 के अन्तर्गत इन्डो यू०एस० एजूकेशन फाउन्डेशन की चर्चा कुछ साल पहले चली थी कि इस देश की शिक्षा की प्रगति के ऊपर उस पैसे को लगाया जाये लेकिन लोक सभा में इस विचार के प्रति काफी विरोध हुआ इसलिए वह चीज स्थगित हो गई लेकिन अब फिर दूसरे दिन ही मि० कीटिंग जोकि अमेरिकन एम्बेसेडर हैं उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है कि इन्डो यू०एस० एजूकेशन फाउंडेशन को रिवाइव किया जाये, उस का माडर्नाइजेशन किया जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री निक्सन से हमारे नेता की जो बात चीत होगी उसमें पी० एल० 480 के सम्बन्ध में भी वार्ता होगी तो मैं जानना चाहूँगा कि पी० एल० 480 के सम्बन्ध में क्या आपकी कोई ऐसी वार्ता हुई कि इन्डो यू०एस० एजूकेशन फाउन्डेशन को रिवाइव किया जाये और उस पैसे को शिक्षा की प्रगति पर लगाया जाये—क्या इस तरह की बातें आपसे हुई हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : जी नहीं, हमारी बातों में यह विषय बिल्कुल नहीं उठा था। लेकिन यह सच है, हमने सुना है कि वे चाहते हैं कि ऐसी कोई फाउन्डेशन हो लेकिन उसकी बात चीत अभी नहीं हुई है। अगर होगी भी तो हमारे देश के हित में क्या होगा, उसको हम हमेशा अपने सामने रखेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहूँगा कि अब कुल मिलाकर कितना पैसा शेष है ? दूसरी बात यह कि अमरीका के राष्ट्रपति के साथ, जैसा कि आपने कहा, पी० एल० 480 के सम्बन्ध में आपकी कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन क्या अमरीकी राजदूतावास या किसी और माध्यम से आपके पास इस प्रकार के सुझाव आये हैं जिनसे सिंचाई, गांवों में बिजली लगाने की योजना या इस प्रकार की जो अन्य योजनायें हैं, उनके ऊपर इस धन का सदुपयोग हो सकता है ? यदि ऐसी कोई योजना आप उनको दें तो उस धन का बहुत बड़ा भाग आप को फिर उन योजनाओं की सहायता के लिए मिल सकता है—यदि यह बात सत्य है तो उसका विवरण क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक पी० एल० 480 फंड्स ऐण्ड लोन्स के बैलेंस की बात है, जैसा मैंने बताया इस वक्त बैलेन्स 77 करोड़ था और इन्ट्रेस्ट 155 करोड़—232 करोड़ के करीब बैलेन्स है। जहां तक उन्होंने कहा कि अमेरिकन इम्बैसी या अमेरिकन एथारिटीज के साथ कोई बातचीत चली है कि इन फंड्स का किस प्रकार से उपयोग हो, माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि हाल ही में रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस रकम में से 105 करोड़ की निधि देने की बात तय हुई है। यह भी तय हुआ है कि बीस करोड़ रुपया फर्टिलाइजर क्रेडिट ग्रांटिंग कारपोरेशन को भी इसमें से दिया जायेगा। इसी प्रकार से उनके साथ मुतवातिर बातचीत की जा रही है कि इस रुपए को यहाँ पर फायदेमन्द कामों पर खर्च किया जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह जैसे यहां के गांवों के विद्युतीकरण आदि की योजनाएं आप ने उन को दी हैं। इस तरीके से सिंचाई की योजनाएं हैं। भारतवर्ष की सबसे प्रमुख समस्या सिंचाई की है। राजस्थान के तमाम इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा आम तौर पर पूरे देश में यह सिंचाई की समस्या बनी हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना पी० एल० 480 के अन्तर्गत आपने दी है कि इस पर मिलने वाला धन लग सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने बतलाया कि जो रुपया बजट द्वारा बतलाया जाता है उसमें से ज्यादातर रुपया एग्रीकलचरल और इर्रीगेशन के कामों पर खर्च किया जा रहा है।

SHRI S. R. DAMANI : Just now, the hon. Minister said that Rs. 105 crores have been agreed for electrification. May I know whether any detailed scheme has been drawn and submitted for electrification in different parts of the country and, if so, the details thereof. Some time back, there was a report that the American Embassy has asked American tourists visiting our country to exchange their dollar with the rupee and, if that is so, may I know the amount that has been so exchanged and the details thereof ?

SHRI P. C. SETHI : As far as the details of Rs. 105 crores are concerned, they will have to be worked out by us. This is only a broad agreement with the United States Emdassy for spending this amount.

As far as the exchange of dollars by American tourists from this fund is concerned, I have no ditalled fnformation with regard to that. But according to be exchange regulations, the foreign country is exchanged with rupees.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : May I just add one thing ? With regard to the rural electrification programme, this scheme has no U. S. involvement in the management or operation of it.

SHRI R. K. AMIN : The hon. Minister knows it very well that any withdrawal from the counterpart funds leads to inflationary trend if there is no fresh budgetary support received from the PL-480 imports. In view of part, as from now onwards we will have ever-decreasing amount of PL-480 transactions and if we at the same time continue to withdraw from the counterpart funds, will it lead to inflation in the country ? May I know what steps have you thought of checking such inflationary pressure and what steps have you taken to freeze the counterpart funds by negotiating with USA.

SHRI P. C. SETHI : As far as PL-480 imports are concerned, they are gradually decreasing. In the year 1968-69, as compared to 1967-68, there will be a decrease of the order of Rs. 215 and odd crores. We hope, by 1971, we shall be in a position when we shall not take PL 480 imports.

As far as the implication on the monetary position is concerned, as I have said most of the amount which is in balance is held in Government securities and what accrues to the U. S. Embassy, according to the negotiations, we are trying to spend for schemes which are of proper use and the money is spent for development programmes.

SHRI R. K. AMIN : When you draw

money from the counterpart funds, it will be inflationary. So, you must freeze the counterpart funds.

SHRI P. C. SETHI : When it is used for developmental purpose, the impact would not be that much on inflationary side.

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह पी. एल. 480 के अन्तर्गत बहुत सी चीजों का जिक्र किया गया है लेकिन देश की जो मुख्य कृषि व सिंचाई की समस्या है और जिसके लिए कि घाघरा, गंडक और नागार्जुन आदि योजनाएं चल रही हैं तो क्यों न उस तमाम रुपये को इस देश के सिंचाई के काम में लगाकर देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय ताकि पी. एल. 480 में हम जल्द से जल्द रिटर्न भी कर सकते हैं, अपने देश का ऐक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, देश के अन्दर खाने, पीने की खुशहाली हो सकती है तो मैं प्रधान मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या वह तमाम रुपये को सिंचाई और कृषि को उन्नत करने में लगाने की सलाह देंगी ? यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया है कि उस रुपये से देश की कृषि को उन्नत किया जाय, डेवलप किया जाय और हर एक व्यक्ति जोकि एकोनामिक्स की ए. बी. सी. जानता है वह मेरे इस विचार से अवश्य सहमत होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में आगे बात करेगी कि यह पी. एल. 480 के अन्दर जितना भी रुपया मिलता है वह तमाम इरीगेशन में लगाया जाय खेती की उन्नति करने में लगाया जाय ;

श्री प्र० चं० सेठी : बजट में हर साल यह बतलाया जाता है कि इस रकम में से कितनी धनराशि इरीगेशन और एग्रीकल्चरल परपेजेज के लिए खर्च होगी...

श्री विभूति मिश्र : मैं चाहता हूं कि वह तमाम के तमाम रुपया सिंचाई और खेती में लगाया जाय। देश में जो सिंचाई की योजनाएं चल रही हैं जैसे घाघरा, गंडक और नागार्जुन योजनाएं आदि हैं उनको पूरा करने में लगाया जाय ताकि हमारा देश खाद्यान्न के मामले में तरक्की कर सके।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायगा।

श्री विभूति मिश्र : यह सुझाव नहीं है अपितु म सरकार से सवाल कर रहा हूँ कि क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ? हम जनता के प्रति निधि होकर यहां चुनकर आये हैं और आप भी जनता के प्रति जिम्मेदार मिनिस्टर हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और जाहिर है कि इसके लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि यह जो रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन का काम है और उसके लिए बजट में रुपया रक्खा गया है तो जाहिर है कि वह सिंचाई के काम में मदद करेगा। इसलिए इन सभी चीजों पर अभी विचार किया जा रहा है लेकिन इस रुपये को किस तरीके से लगाया जाय इसमें बहुत से पेंच भी है।

SHRI SWELL : It would appear from the reply of the Minister of State that the total balance of P. L. 480 funds with us amounts to only Rs. 232 crores. Reports from other sources say that the total accumulation of PL 480 funds in this country has risen to Rs. 2250 crores. I would like the Government to confirm or to deny these reports.

I would like to know whether the Government has broadly reached an understanding with the Government of the United States of America with regard to the utilisation of these funds. In particular, I would like to know whether the question of the Indo-U.S. Education Foundation in this country has been revised. The Prime Minister said that no question of Americation control over the Rural Electrification Corporation was involved. Now that we have the schemes for setting up of two other Corporations, the Fertiliser Credit Corporation, and the Agricultural Refinance Corporation, I would like to know

whether any definance decision has been reached with regard to these two other Corporations and whether American control is any way involved in these.

SHRI P. C. SETHI : I think, there is some misunderstanding as for as the total amount is concerned. I have said that the total amount which has accrued on account PL 480 fund and other loans and grants from the United States is Rs. 2,117.03 crores. The hon. Member is right as far as this is concerned. What I have said is this. Out of this amount, a major portion has been spent on government works. About Rs. 232.23 crores will be the total which will pass on to the U.S. Embassy and out of this, I have indicated the figure of Rs. 105 crores which are to be spent for rural electrification through the Corporation. As far as the Fertiliser Credit Guarantee Corporation is concerned, that is under negotiation for Rs. 20 crores of expenditure and it is on similar lines as the rural Electrification Corporation.

SHRI SWELL : I had also asked whether the question of Indo-U. S. Education Foudation had been revised. That is a very important question.

SHRI P. C. SETHI : The Prime Minister has already said about it.

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या माननीय मंत्री का ध्यान अमरीका के राजदूत के दिल्ली में दिए गये हाल के उस वक्तव्य की ओर गया है जिस में उन्होंने कहा है कि पी. एल. 480 के अन्तर्गत समय-समय पर जो भारत सरकार को सहायता दी जाती है हाल ही में थोड़े दिनों के अन्दर ही वह रुपया 1500 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ के बीच में हो जायगा ? उन्होंने यह भी यह भी कहा है कि यह बढ़ती हुई रकम अमरीका और भारत दोनों की ही सरकारों के लिए चिन्ता का विषय बन रहा है और इसलिए वह इसके ऊपर भारत सरकार से उच्च स्तर पर विशेष रूप से बातचीत करना चाहते हैं ? क्या यह बात भी सही नहीं है कि कई बार इस सदन ने और इस सदन की समिति से भी यह सुझाव दिया है कि इस रुपये के इकट्ठा होने से मुद्रास्फीति होगी ? खास कर खुसरो कमेटी ने भी इस ओर सरकार का ध्यान खींचा है कि इस रुपये का बढ़ाव हमारे देश की मुद्रास्फीति पर पड़ रहा है और इसलिए इस रुपये का ठीक से प्रयोग हो सके और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक अमरीका की सरकार से वार्त्ता करने का ताल्लुक है, तो अमरीकी सरकार से इस बात पर निरन्तर समय समय पर वार्त्ता होती रहती है और हो रही है कि इस रु० को किस प्रकार से खर्च किया जाय ताकि मुद्रास्फीति न बढ़े ।

जहां तक इस रकम का सवाल है मैंने बताया कि कुल कितनी रकम है । आइन्दा भी जो इसकी वापसी करनी होगी वह करीब 40, 50 करोड़ रु० हर साल के हिसाब वापसी करनी होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा पहला प्रश्न यह था कि भारत में अमरीका के राजदूत ने खुद यह कहा है कि यह बढ़ती हुई रकम दोनों सरकारों के लिए चिन्ता का विषय है और इसलिए उन्होंने खुद कहा है कि हम भारत सरकार से उच्च स्तर पर वार्ता करना चाहते हैं । खुसरो कमेटी ने भी यह सिफारिश की है कि इसका मुद्रास्फीति पर असर पड़ रहा है । उसके संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक रुपये का ताल्लुक है इस पर समय-समय पर वार्ता हुई है और अभी भी हो रही है, और इस रुपये का ठीक से विनियम हो इस बात पर हमेशा ऊंचे स्तर पर चर्चा आइंदा भी हो सकती है । अभी भी कभी-कभी उसके सम्बन्ध में उनके साथ विचार विनियम हुआ है ।

जहां तक मुद्रास्फीति का सवाल है, यह

स्पष्ट है कि वही रकम जो बैलेंस के रूप में बची है जिसका मैंने जिक्र किया, वह 677 करोड़ रु० है, वह गवर्नमेंट सैक्योरिटीज़ में इन-वेस्टेड है और उसी में से कुछ रकम, 200 करोड़ रु० के करीब यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में गयी है और वह सर्कुलेशन में आकर मुद्रास्फीति न करे उसके लिए विचार हो रहा है कि किस प्रकार उसका विनियम किया जाए ताकि उसका बुरा असर न पड़े। और जैसा मैंने कहा हर साल जो 30-40 साल तक रुपया वापस करना होगा, 50 करोड़ रु० हर साल जमा होता जायगा तो वह भी मुद्रास्फीति को न बढ़ाये उसका ध्यान रखते हुए उनसे विचार विनियम करते हुए उस का खर्चा किया जायगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या पी० एल० 480 का उपयोग किया जायगा जो देश के अन्दर एक बहुत बड़ा कलंक है कि बाजारों में, सड़कों पर जो बहुत बड़ी संख्या में भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं और विदेश के लोग जब उन को देखते हैं तो भारत के बारे में एक बुरा प्रभाव अपने मन में लेकर जाते हैं जिसके कारण हमको बहुत लज्जित होना पड़ता है। यह जो भिक्षा-वृत्ति बनी हुई है इसको समाप्त करने के लिए क्या इस पैसे का उपयोग सरकार करेगी ? या देश में जो बहुत से बूढ़े बेकार लोग हैं ऐसे बूढ़ों के लिए कोई पेंशन की योजना लागू करना चाहती है ?

Pak Smugglers

*302. SHRI RAM CHARAN :
SHRI BANSH NARAIN SINGH :
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :
SHRI S. M. BANERJEE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that seven Pakistani smugglers escaped recently from the police custody in Mandvi as reported in the *Statesman* of the 18 May, 1969 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the action taken against police officials responsible for this ; and

(d) whether those Pakistani smugglers have been arrested and deported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) to (d). Seven Pakistani crew members of M.S.V. Mai Makai who were found in the vessel when she was intercepted by the Indian Naval vessel in the Indian territorial waters of Kutch Coast on 7-2-68 were proceeded against for voilation of the provisions of the Foreigners' Registration Act and the Passport regulations and were convicted. On completion of period of imprisonment, they were under police surveillance pending deportation to Pakistan. The seven persons however managed to escape on 16-5-69. They have not been apprehended so far. Six police constables and one head constable have been placed under suspension for derelliction of duty.

श्री राम चरण : यह कोई नई बात नहीं है, बार्डर पर पाकिस्तान, चीन और नेपाल से काफ़ी स्मगलिंग हो रहा है, और रोज़ाना वहां पर हो रहा है। पुलिस स्मगलर्स से मिली हुई है। अगर कभी लोग पिक्चर में आ जाते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और थोड़े दिन सज़ा करके छोड़ देती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बार्डर से पाकिस्तान, चीन और नेपाल को जो यहां से राशन जाता है इस बारे में आपने कोई स्टैप्स लिये हैं ताकि इस प्रकार की स्मगलिंग बार्डर पर न हुआ करे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक स्मगलिंग को रोकने का ताल्लुक है इसके सम्बन्ध में कई कार्यवाहियां की गयी हैं। उदाहरण के तौर पर स्टाफ़ बढ़ाया गया है और उन्हें कनवेयेंस और मोडर्न एक्विपमेंट्स आदि की सुविधायें बढ़ाई गई हैं। कस्टम्स बिल में भी अभी संशोधन किया गया है। इसके अलावा सेन्ट्रल रिज़र्व